



# गाथा

हमारा

वौपाल से  
भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 08-14 नवंबर 2021, वर्ष-7, अंक-32

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ:-8, मूल्य:- 2 रुपए

एनसीआरबी रिपोर्ट ने किया खुलासा, मप्र में घटे आंकड़े, खुशहाली की ओर अग्रसर किसान

» 2020: सबसे अधिक 33,164 दिहाड़ी मजदूरों ने की आत्महत्या  
» खेती किसानों से जुड़े लोगों की आत्महत्याओं के आंकड़ों में वृद्धि

## देश में रोजाना 30 किसान और कृषि मजदूर कर रहे आत्महत्या

अरविंद मिश्रा | भोपाल

भारत में रोजाना 30 किसान और खेतिहर मजदूर आत्महत्या करते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में कृषि क्षेत्र में शामिल कुल 10,667 लोगों ने आत्महत्या की, जिसमें 5579 किसान और 5098 खेतिहर मजदूर शामिल हैं। साल 2020 में देश में कुल 153,052 लोगों ने आत्महत्या की थी, जिसमें से कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों का प्रतिशत सात है। अक्टूबर 2021 की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश में कृषि मजदूरों की आत्महत्या की दर में 18 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। साल 2019 में 4324 कृषि मजदूरों ने आत्महत्या की थी, जबकि 2020 में ये संख्या बढ़कर 5098 हो गई है। हालांकि किसानों की आत्महत्या की दर में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। किसानों की आत्महत्या के मामलों की संख्या 2019 में 5957 से घटकर 2020 में 5579 हो गई, आंकड़ों के मुताबिक 6 फीसदी की गिरावट है। 2020 में जिन 5579 किसानों ने आत्महत्या की उसमें से 95.6 फीसदी पुरुष और 4.4 फीसदी महिलाएं थी, जबकि खेतिहर मजदूरों की बात करें तो 5098 आत्महत्याओं में 90.6 फीसदी पुरुष और 9.3 फीसदी महिलाएं थी।

2017-18: के आंकड़े

तेलंगाना 846

मध्य प्रदेश 429

आंध्र प्रदेश 375

तेलंगाना 900

आंध्र प्रदेश 365

मध्य प्रदेश 303



2019 में 28 किसानों ने प्रतिदिन दी जान

कुछ खास

» साल 2020 में सबसे अधिक आत्महत्याएं (24.6 प्रतिशत) दिहाड़ी मजदूरों ने की, जबकि साल 2019 में यह प्रतिशत 23.4 था। 2020 में 33,164 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की, जबकि 2019 में 29,092 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की।  
» 2020 में 10,677 ऐसे लोगों ने आत्महत्या की, जो कृषि क्षेत्र से जुड़े थे। यानी कि 5,579 किसानों और 5,098 खेतिहर मजदूरों ने आत्महत्या की। जबकि 2019 में 5,957 किसानों और 4,324

खेतिहर मजदूरों (कुल 10,281) ने आत्महत्या की।

» 2017 में मजदूरों ने सबसे अधिक आत्महत्या की। इस साल 28,737 मजदूरों ने आत्महत्या की, जबकि खेती किसानों से जुड़े लोगों की संख्या में कमी आई और उनकी संख्या 10,655 रही।

» 2018 में आत्महत्या करने वालों में दैनिक वेतनभोगी मजदूरों का प्रतिशत 22.4 रहा। इस 9.4 प्रतिशत बेरोजगारों ने आत्महत्या की, जबकि खेती किसानों से जुड़े लोगों की संख्या 7.7 प्रतिशत रही। खेती किसानों से जुड़े 10,349 लोगों ने आत्महत्या की।

कृषि श्रमिक भी दे रहे जान

मजदूरों की आत्महत्या की दर बढ़ गई है। साल 2019 में 32559 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की जो 2018 में जान देने वाले 30132 कामगारों के मुकाबले 08 फीसदी ज्यादा है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि साल 2019 में जिन 10281 किसानों ने जान दी है, उनमें 5957 किसान और 4324 कृषि मजदूर शामिल हैं। साल 2019 में हुई कुल आत्महत्या में कृषि की हिस्सेदारी 7.4 फीसदी है। जिन किसानों ने साल 2019 में जान दी है उनमें 394 महिला की हैं, जबकि मजदूरों की बात करें तो 574 महिला कृषि मजदूरों ने आत्महत्या की है।

शिवराज में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते अन्नदाता

खेती किसानों से जुड़े लोगों ने सबसे अधिक महाराष्ट्र में आत्महत्याएं की। यहां 117, बिहार में 13, हिमाचल प्रदेश में 24, झारखंड में 17, सिक्किम में 16, 4006 किसानों-खेतिहर मजदूरों ने आत्महत्या की। इसके बाद कर्नाटक में 2016, आंध्र प्रदेश में 889, मध्य प्रदेश में 735, छत्तीसगढ़ में 537, तमिलनाडु में 477, तेलंगाना में 471, ओडिशा में 7, मणिपुर में 1, मेघालय में 5, मिजोरम में 4 किसानों व खेतिहर मजदूरों ने आत्महत्या की। उक्त आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि मप्र में अब हालात सुधर गए हैं। किसान खुशहाल हैं और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि शिवराज में किसान आत्महत्या नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं।



केंद्रीय जनजातीय विवि अमरकंटक और सीधी प्रशासन के प्रयास से सोनांचल कोदो को मिलेगी पहचान

## आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने प्रदेश में 'कोदो क्रांति'

संवाददाता | सीधी

दशकों तक गरीबों की थाली के अनाज के रूप में कोदो की पहचान रही है। अब गरीबों का यह अनाज अपने पौष्टिक गुणों के कारण हर तबके में अपनी पहुंच बना रहा है। हम बात कर रहे हैं मप्र के जनजातीय बाहुल्य जिलों की, यहां की महिलाओं ने कोदो को अपनी आजीविका के प्रमुख संसाधनों से जोड़ा है। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति के बाद अब मध्यप्रदेश के आदिवासी अंचल में 'कोदो क्रांति' की शुरुआत की गई है। आदिवासी बाहुल्य सीधी जिले ने भी पारंपरिक अनाज कोदो को सुपर मार्केट तक पहुंचाने की ओर कदम बढ़ाए हैं। अपने औषधीय गुणों के बीच कोदो की बढ़ती डिमांड ने महिला समूहों के सशक्त आजीविका की राहों को आसान किया है। केंद्रीय जनजातीय विवि अमरकंटक और सीधी जिला प्रशासन के प्रयासों के बाद जल्द ही

जनजातीय महिलाओं द्वारा निर्मित सोनांचल कोदो उत्पाद सुपर मार्केट तक पहुंचेगा। अनूपपुर जिले में स्थापित देश के पहली जनजातीय विवि के साथ मिलकर सीधी जिला प्रशासन ने आत्मनिर्भर मप्र को साकार करने की कवायद में आगे आया है।  
**अपना ब्रांड 'सोनांचल कोदो'**

महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ने बताया है कि आत्मनिर्भर मप्र रोडमैप 2023 के तहत एक जिला एक उत्पाद योजनांतर्गत सीधी जिले में चयनित उत्पाद कोदो को एक नई पहचान मिलने जा रहा है। सोनांचल कोदो किसी भी रूप में बाजार में मिलने वाले अन्य स्थापित ब्रांड से कमतर नहीं है। यह एक सुखद आश्चर्य है कि सीधी जैसे सुदूर जिले से इतनी जल्दी स्तरीय ब्रांड तैयार किया जा सका है। जिले के सिहावल और कुसमी की कोदो प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित की गई हैं।



छोटे अनाजों की बाजार में बढ़ती मांग ने जनजातीय वर्ग के लोगों को स्व-रोजगार के नए अवसर दिए हैं। आत्मनिर्भर प्रदेश की परिकल्पना में सीधी जिले की जनजातीय महिलाओं ने नए आयाम की शुरुआत की गई है। जल्द ही महिलाओं की मेहनत सोनांचल कोदो के रूप में दिखाई देगी।  
रीति पाठक, सांसद, सीधी

गांव ही विकास की प्राथमिक ईकाई

देश की एक तिहाई आबादी गांव में रहती है। ग्रामीणों को उनके घर में ही रोजगार उपलब्ध कराते हुए हम आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। इन अनाजों की लोकप्रियता लोगों के बीच है, लेकिन उपलब्धता का अभाव भी है। कोदो प्रसंस्करण और उसे उचित बाजार तक पहुंचा कर हम ग्रामीणों एवं उपभोक्ता दोनों को ही फायदा पहुंचा सकते हैं। महिलाओं का ब्रांडिंग और मार्केटिंग को लेकर बढ़ता रुझान आने वाले स्वर्णिम समय का परिचायक है। हम मिलते कॉरीडोर को तैयार करने के लिए शासन-प्रशासन के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं।  
प्रो. श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी, कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विवि, अमरकंटक

वर्ष वार आत्महत्या का आंकड़ा

2004	1638	2011	1326
2005	1248	2012	1172
2006	1375	2013	1090
2007	1263	2014	826
2008	1379	2015	581
2009	1395	2016	599
2010	1237		



## अयोध्या में ऐतिहासिक दीपोत्सव के साक्षी बने मप्र के कृषि मंत्री कमल पटेल

भोपाल। अयोध्या में 5वें भव्य दीपोत्सव समारोह में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अयोध्या में प्रभु श्रीराम के भक्तों ने 9.51 लाख दीपक एक साथ जलाकर विश्व कीर्तिमान रच दिया। सौभाग्यवश यह मनोरम दृश्य देखने का अवसर मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी टीम को ऐतिहासिक और सफल आयोजन की बधाई। उन्होंने कहा कि हम कहते थे राम लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन कर एवं रामलाल के भव्य मंदिर का निर्माण देखकर जीवन सार्थक हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम भारतीय इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और विश्वास का प्रतीक हैं।

## प्रदेश में फूल गोभी का रकबा 293.40 लाख हेक्टेयर: फूलगोभी के पत्ते हरे पर फूल बहुत कम लगे

# गोभी वाले गांव के किसान परेशान

संवाददाता। सतना

करीब 15 सालों से खरीफ की उड़द, मूंग, तिल और धान जैसी फसलों के साथ ही ज्यादा मुनाफे के लिए फूलगोभी के खेती करने वाले किसान इस साल की फसल का रुख देख कर परेशान हैं। फूल गोभी की फसल में इस बार पत्तियां तो खूब हरी-भरी हैं, लेकिन फूल बहुत कम आए हैं। अपने गोभी के खेत में गुड़ई कर रहे राम सिया कुशवाहा (46 वर्ष) ने बताया कि 15-20 सालों से धान के अलावा फूल गोभी की खेती करते आ रहे हैं।

यह पहली बार है जब गोभी में समय पर फूल नहीं आए हैं। यह दो महीने की फसल है, लेकिन इस बार खराब हो गई। राम सिया सतना जिले के गांव भरी के बटाईदार किसान हैं। उन्होंने तीन एकड़ में फूलगोभी लगा रखी है। उनके गांव और आप-पास के कई गांवों में किसान गोभी की खेती करते हैं। राम सिया कहते हैं कि रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने के लिए फूल गोभी की खेती करते हैं। इस साल 8000 रुपए का बीज लिया था। लेकिन खराब हो गया। मध्य प्रदेश में करीब 293.40 लाख हेक्टेयर में फूल गोभी की खेती होती है। इसमें सतना जिला में लगभग 2000 हेक्टेयर का सहयोग करता है। यह रकबा लगातार बढ़ भी रहा, जबकि उत्पादन 50 हजार मीट्रिक टन से भी ज्यादा है।

## उचेहरा, नागौद, अमरपाटन, रीवा जिले हनुमना और अब सीधी में गोभी की खेती



उद्यान विभाग के उपसंचालक नारायण सिंह कुशवाहा ने तृतीय अनुमान वर्ष 2021 के आंकड़े साझा करते हुए बताया। सतना में फूल गोभी का दोनों सीजन के कुल रकबा 1812.000 हेक्टेयर है जिसमें से खरीफ का 579.000 (इकाई हजार) हेक्टेयर और रबी सीजन के 1233.000 हेक्टेयर है। उत्पादन की बात करें तो कुल 51833.000 मीट्रिक टन है जिसमें खरीफ 4905.000 मीट्रिक टन और रबी का 43632.000 मीट्रिक टन है।

## 75 फीसदी किसान कर रहे फूल गोभी की खेती

सतना जिले के उचेहरा ब्लॉक के 75 फीसदी किसान खरीफ सीजन में अनाज के अलावा सब्जियां उगा रहे हैं। उचेहरा ब्लॉक के भरी, तुरी, अटरा, घोरहटी और उदिया गांव को गोभी वाले गांव के नाम से भी लोग पुकारते हैं। 15 सालों से फूल गोभी की खेती करने वाले रामसिया बताते हैं कि करीब 500 एकड़ में फूल गोभी की खेती हो रही है। कुछ तो 15 सालों से करते आ रहे हैं, कुछ पिछले आठ सालों से। इस तरह से यहां के पांच गांव के 75 फीसदी किसान फूल गोभी लगा रहे हैं। यह यहां अब चलन में है। किसान एक-दूसरे की देखा देखी फूल गोभी उगा रहे हैं।

## विंध्य में हो रही खेती

उद्यानिकी वैज्ञानिकों का मानना है कि फूल गोभी में फूल न आने की वजह एक ही है किसान जल्दी उत्पादन चाहता है और वह पहले बो देता है। रीवा जिले के उद्यानिकी वैज्ञानिक डॉ. राजेश सिंह ने बताते हैं कि गोभी में फूल न आने की बड़ी वजह किसानों द्वारा जल्दी बुवाई करना है। आपने जो फील्ड में देखा होगा वह फसल जुलाई के अंतिम सप्ताह की हो सकती है। जबकि यह केवल 60 दिनों की ही फसल है। इतने दिन में फूल बढ़िया आ जाते हैं। किसानों को बिल्कुल भी यूरिया नहीं उपयोग में लानी चाहिए। इससे पौधा और बढ़ सकता है जिससे फूल प्रभावित होगा। विंध्य में फूल गोभी की खेती बढ़ रही है। सतना जिले के उचेहरा, नागौद, अमरपाटन रीवा जिले हनुमना और अब सीधी जिले में भी हो रही है।

## आलू प्रसंस्करण इकाइयों का भूमि पूजन और कृषक प्रशिक्षण सम्पन्न

संवाददाता। इंदौर

आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत आत्म निर्भर मध्यप्रदेश निर्माण में मध्यप्रदेश स्थापना दिवस 1 नवम्बर को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना अंतर्गत 35 प्रतिशत अनुदान (व्यक्तिगत उद्यम में अधिकतम 10 लाख) प्रोत्साहन पर, एक जिला एक उत्पाद में चयनित फसल आलू उत्पाद प्रसंस्करण आधारित चिप्स निर्माण इकाई स्थापना के शुभारम्भ कलेक्टर इंदौर मनीष सिंह के निर्देशन में, अपर कलेक्टर अभय बेडेकर के मार्गदर्शन और उपायुक्त सहकारिता एम गजभिए के सहयोग से एक जिला एक उत्पाद में चयनित फसल आलू प्रसंस्करण स्थापना इकाई के लिए ग्राम पेडमी में राजवीर डावर के प्रक्षेत्र पर डावर एवं अन्य दो किसान मनोहर पाटीदार और श्याम पाटीदार की योजना अंतर्गत परियोजना लागत राशि 1-34 करोड़ कुल संख्या 03 स्वीकृत इकाई स्थापना



का भूमि पूजन एवं कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें किसानों को आलू फसल उत्पादन की उन्नत फसल तकनीकी एवं आलू फसल आधारित प्रसंस्करण उत्पाद जैसे आलू चिप्स, फ्रेंच प्राइज, पावडर, स्टार्च इत्यादि प्रसंस्करण मशीनों/तकनीकी, रबी मौसम आधारित उद्यानिकी फसल पौध संरक्षण एवं रख-रखाव के जैविक तरीकों और औषधीय

फसलों की जैविक खेती की उन्नत तकनीकी जानकारी दी गई। पेडमी में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मंत्री तुलसी सिलावट के प्रतिनिधि रवि दुबे थे। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉ. अशोक शर्मा अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय इंदौर, डॉ. किराडु अतिरिक्त संचालक उद्यानिकी भोपाल, डॉ. एच एस ठाकुर वैज्ञानिक, डॉ. स्वाति बाचें वैज्ञानिक और सरपंच पेडमी थे। इस आयोजन में विकास खंड इंदौर के स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रगतिशील कृषक, उद्यानिकी विभाग सांवेर विकास खंड प्रभारी वीके कुशवाहा, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी पूजा शुक्ला, दीपिका मुजाल्दे, एनके जोशी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ उद्यान विस्तार अधिकारी मनोज कुमार यादव ने किया और आभार प्रदर्शन एस एस शक्तावत उद्यान विकास अधिकारी, कार्यालय उपसंचालक इंदौर द्वारा किया गया।

## दुग्ध उत्पाद पर देंगे व्यवसायिक प्रशिक्षण



गवालियर। कृषि विज्ञान केन्द्र, गवालियर द्वारा 9 से 13 नवंबर तक दुग्ध उत्पाद पर व्यवसायिक प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक कृषक एवं कृषक महिलाएं कृषि विज्ञान केन्द्र गवालियर, में आकर सम्पर्क करें। वहीं कड़कनाथ मुर्गा पालन पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन से 13 नवंबर किया जा रहा है। आर्या परियोजना के तहत चयनित युवा कृषक अवश्य भाग लें। कृषि विज्ञान केन्द्र, गवालियर द्वारा 15 से 19 नवंबर

तक आर्या परियोजना के अन्तर्गत बकरी पालन पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। आर्या परियोजना के अन्तर्गत चयनित युवा कृषक अवश्य भाग लें। कृषि विज्ञान केन्द्र, गवालियर द्वारा दिनांक 22 से 26 नवंबर तक आर्या परियोजना के अन्तर्गत नर्सरी प्रबंधन पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आर्या परियोजना के अन्तर्गत चयनित युवा कृषक अवश्य भाग लें।

» दिल्ली में निखारी माटी की कला, कोलकाता और हरियाणा भी गए

» कई राज्यों के अलावा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तक भी गया सामान

» सीजन के हिसाब से कमाई पर साल का 3-4 लाख की आमदनी

## अमल को दिल्ली से खींच लाई गांव की माटी

सतना। बचपन में आपने भी अपनी छोटी, छोटी कल्पनाओं को माटी में सजाया-संवारा होगा। उसे कोई न कोई आकार दिया होगा। अमल माझी भी उन्हीं में से एक हैं। उनका माटी प्रेम बचपन के हाथी, घोड़ा बनाने से ही शुरू हुआ था। जो आज बड़े कारोबार का रूप ले चुका है। अब उनके हाथों का हुनर देश के कोने-कोने तक पहुंच रहा है। 48 वर्षीय अमल सतना जिले के गांव महतैन के वाले हैं। जहां वह अपनी कल्पनाओं को माटी के सहारे साकार कर रहे हैं। अमल पहले दिल्ली में यहीं काम करते थे।



## किसानों के काम का शोध: असंभव को आरजीपीवी ने किया संभव डीजल वाहन सीएनजी से चलाएं खेती में होने वाला बचेगा खर्च

विशेष संवाददाता, भोपाल।

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विवि ने किसानों के काम के शोध करके असंभव को संभव कर दिया है। दरअलस, पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम की वजह से अब सीएनजी को लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में डीजल वाहन सीएनजी में कन्वर्ट नहीं होते हैं। इसे देखते हुए आरजीपीवी में एक शोध हुआ है। इसके तहत डीजल इंजन में तकनीकी बदलाव कर वाहन को सीएनजी से चलाया जा सकेगा और पेट्रोल का भी उपयोग किया जा सकेगा।

रिसर्च करने वाली फैकल्टी के मुताबिक रिसर्च में डीजल वाहन को पेट्रोल और सीएनजी से चलाने पर काम किया गया है। डीजल वाहनों को अगर सीएनजी या अन्य सस्ते ईंधन से चलाया जा सके तो इसका लाभ किसानों को खेती में भी मिल सकेगा। रिसर्च करने वाले आरजीपीवी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एचओडी प्रो. असीम तिवारी ने बताया कि इसके लिए पेटेंट फाइल किए गए हैं। उन्होंने बताया कि छोटे वाहनों में डीजल इंजन धीरे-धीरे बंद हो रहे हैं। इस वजह से आने वाले समय में इनका रखरखाव भी अपेक्षाकृत महंगा पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अगर यह सीएनजी या अन्य तरह के सस्ते फ्यूल से चलेंगे तो इसका सीधा लाभ वाहन चालक को मिल सकेगा। बड़े वाहनों में भी यह काफी उपयोगी साबित होगा।



### किसानों के लिए उपयोगी

खासकर कृषि में इस्तेमाल होने वाले वाहनों में इसके उपयोग से किसानों को लाभ मिलेगा, खेती में होने वाले खर्च में कमी आएगी। रिसर्च के मुताबिक हार्वेस्टर सहित अन्य बड़े वाहनों में डीजल की काफी खपत होती है। अगर ये पेट्रोल के साथ सीएनजी से चलेंगे तो लागत में काफी कमी आ आएगी।

### वाहन चालक को भी फायदा

अब लोग इलेक्ट्रिक कार की पूछ-परख भी करने लगे हैं, लेकिन वर्तमान में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, उनका एसी बैटरी से चलता है। इस वजह से बैटरी की लाइफ काफी प्रभावित होती है। इसका हल भी आरजीपीवी ने निकाल लिया है। यहां ऐसी टेक्निक पर काम हो रहा है, जिसमें एसी चलाने के लिए बैटरी की जरूरत न के बराबर पड़ेगी। इससे बैटरी की लाइफ में बढ़ोतरी होगी और इलेक्ट्रिक वाहन चालक को फायदा होगा।

## ब्रेक के पावर का उपयोग करेंगे

आरजीपीवी के मैकेनिकल डिपार्टमेंट के एचओडी प्रो. असीम तिवारी ने बताया कि वर्तमान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एसी, पेट्रोल और डीजल कारों के सिस्टम की तरह ही काम करता है। यह कंप्रेसर बेस्ड होता है। इस वजह से यह बैटरी के पावर को कम करता है। इसे देखते हुए ऐसी तकनीक पर काम किया जा रहा है, जिससे दूसरे सोर्स से कार के एसी को चलाया जा सके। इसमें ब्रेक के अलावा डीसी मोटर से हीट लेने जैसे विकल्प को शामिल किया जा रहा है। अभी वेपर कंप्रेसर सिस्टम पर काम होता है। इस दिशा में करीब एक साल से रिसर्च जारी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी की लाइफ तीन साल होती है।

## हरियाणा और एमपी के उन्नत किसान मिलकर करेंगे खेती

### कृषि मंत्री बोले-खाद की किल्लत नहीं, जमाखोरों पर हो रही कार्रवाई

जबलपुर। प्रदेश के किसानों के लिए पर्याप्त खाद उपलब्ध है। सहकारी संस्थान से लेकर व्यापारियों तक खाद का स्टॉफ रखा है। यह सच बात है कि कुछ जमाखोरों ने गलत तरीके से खाद का स्टॉक करके उसकी किलर पैदा की थी, लेकिन हमने उनके खिलाफ कार्रवाई कर उनके प्रयास को सफल नहीं होने दिया। यह बात प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि खाद वितरण का अधिकार सिर्फ सहकारी संस्थानों को नहीं दिया है। उनके पास 75 फीसदी का स्टॉक रखा गया है, बाकी 25 फीसदी व्यापारियों को उपलब्ध कराई गई है, ताकि किसान उन से सीधे तौर पर खाद ले सकें। कृषि मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के दाम कम करके आम लोगों को ही नहीं, बल्कि किसानों को भी राहत दी गई है ताकि

वह अपनी खेती की लागत को नियंत्रित कर सके। कोरोना काल के दौरान जैविक खेती का महत्व बढ़ा है। प्रदेश सरकार किसानों जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इसके लिए प्रदेश स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। खास तौर पर उन जिलों को लिया जाएगा, जहां आज भी जैविक खाद का उपयोग कर खेती की जा रही है। इन ट्राइबल जिलों को जैविक खेती का माडल बनाकर प्रदेश स्तर पर इनकी ब्रांडिंग की जाएगी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के जबलपुर प्रवास को लेकर उन्होंने कहा कि वह मेरे दोस्त हैं। उन्होंने शहर की हरियाली और उपजाऊ जमीन को इतना पसंद किया कि उन्होंने ललपुर में अपना फार्म हाउस बनाया है। प्रदेश सरकार जल्द ही दोनों राज्यों के उन्नत किसानों को एकजुट कर खेती में नए उपयोग करेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि जबलपुर कृषि विवि के विज्ञानिकों और प्रोफेसरों को हर हाल में सातवां वेतनमान मिलना चाहिए।

## कृषि विवि में एनबीपीजीआर टीम ने किया अनुसंधान कार्यों का निरीक्षण

जबलपुर। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित तिल एवं रामतिल परियोजना में चल रहे, डीबीटी प्रोजेक्ट के अनुसंधान के कार्यों का निरीक्षण एनबीपीजीआर के पूर्व निदेशक व वर्तमान में जीन बैंक प्रमुख, आईसीआरआईएसएटी डॉ. कुलदीप सिंह, एनबीपीजीआर के निदेशक डॉ. अशोक कुमार, विभागाध्यक्ष पादप रोग विभाग आईएआरआई नई दिल्ली डॉ. जीपी राव एवं प्रमुख वैज्ञानिक एनबीपीजीआर नई दिल्ली डॉ. रश्मि यादव द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉ. कुलदीप सिंह द्वारा कृषि महाविद्यालय

जबलपुर के विवेकानंद सभागार में जैव विविधता विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। जिससे विवि के सभी प्राध्यापकगण एवं विद्यार्थी लाभान्वित हुए। उक्त व्याख्यान में उन्होंने जैवविविधता का महत्व बताया एवं विवि के वैज्ञानिकों को चिरोंजी की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान संचालक शिक्षण डॉ. अभिषेक शुक्ला, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय डॉ. शरद तिवारी, अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. अमित कुमार शर्मा एवं तिल एवं रामतिल परियोजना की समन्वयक डॉ. रजनी बिसेन की उपस्थिति रही।



डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह  
प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, शिवपुरी

# स्वदेशी पशुधन पर संकट के बादल

किसी राष्ट्र, राज्य या क्षेत्र की पहचान उसकी संस्कृति, स्थानीय भाषा, रहन-सहन, खानपान यहां तक कि वहां पाई जाने वाली स्थानीय स्वदेशी पशुओं की नस्लों को लेकर होती है, लेकिन जब उसकी यही विशेषताएं ही धीरे-धीरे करके विलुप्त होने लगे तो चिंता होना लाजमी है। वर्तमान में ऐसा ही कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश की स्थानीय स्वदेशी डेयरी पशुओं की नस्लों को लेकर। राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी विशेषताओं को लेकर जानी पहचानी जाने वाली गायों और भैंस की नस्लों को लेकर चिंता होना स्वाभाविक है। ऐसा क्यों हो रहा है इसके पीछे मुख्य वजह क्या है प्रमुख तौर पर जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसके अनुसार स्थानीय गायों और भैंस की नस्लों में दुग्ध उत्पादकता का कम होना है। साथ ही मशीनी युग में बछड़ों का प्रयोग नगण्य होते चले जाना है।

मध्य प्रदेश में गायों की स्थानीय स्वदेशी नस्लों की तरफ से किसानों का रुझान कम होता जा रहा है। प्रदेश में प्रमुख रूप से गायों की चार स्वदेशी नस्ल पाई जाती हैं। जिनमें कैनकथा, मालवी, निमाड़ी तथा ग्वालों गाय प्रमुख हैं। कैनकथा बुंदेलखण्ड में, मालवी नस्ल मालवा में, निमाड़ी नस्ल निमाड़ में तथा ग्वालो महाकौशल में पाई जाती हैं। गायों के संरक्षण के नाम पर दुग्ध उत्पादक विदेशी गायों की नस्लों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ किसानों का गाय पालन के प्रति घटते रुझान के पीछे मुख्य कारणों में स्थानीय देशी गायों में दुग्ध उत्पादकता कम होने के साथ ही गाय के दूध का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाना है। गाय के बछड़ों का भी कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस कारण किसान-पशुपालकों को लगने लगा है कि गाय पालन घाटे का सौदा बनता जा रहा है। गायों के संरक्षण के नाम पर आज राज्य की चारों स्थानीय देशी नस्लों के संरक्षण पर कहीं कोई बात नहीं हो रही है। सिर्फ अन्य राज्यों की अधिक दूध देने वाली दुधरू गायों की नस्लें जिनमें प्रमुख तौर पर विदेशी क्रॉस ब्रीड नस्ल की गायों को ज्यादा संरक्षण दिया जा रहा है। ऐसा ही होता रहा तो आने वाले कुछ दशकों में राज्य से स्थानीय देशी गायों की नस्लों को विलुप्त होने से रोख पाना मुश्किल होगा।

राज्य की प्रमुख स्वदेशी गायों में कैनकथा नस्ल के पशु प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर तथा उत्तर प्रदेश के ललितपुर, हमीरपुर, बांदा आदि जिलों में पाये जाते हैं। जिनका प्रमुख तौर पर भारवाहन के कार्यों में ही उपयोग किया जाता है। इस नस्ल में प्रति ब्यांत औसत दूध देने की क्षमता लगभग 500 से लेकर 600 किग्रा तक है। मालवी मालवा क्षेत्र की यह एक प्रमुख गाय की नस्ल है। इसी कारण इस नस्ल का मालवी नाम इसके मूल स्थान के नाम पर रखा गया है। यह नस्ल प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश

के राजगढ़, शाजापुर, रतलाम और उज्जैन जिले में पायी जाती है। इस नस्ल में प्रति ब्यांत औसत दूध देने की क्षमता लगभग 900 से लेकर 1200 किग्रा तक है। इसी प्रकार से निमाड़ी गाय मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र की प्रमुख नस्ल है। जिसका नाम भी इसके मूल स्थान मध्य



प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के नाम पर ही रखा गया है। यह नस्ल मध्य प्रदेश के खरगौन, बड़वानी, इंदौर आदि जिले में पायी जाती है। इसके प्रजनन पथ में मध्य प्रदेश के खरगौन (पश्चिम निमाड़) और बड़वानी जिले शामिल हैं। इस नस्ल की गाय औसतन प्रति ब्यांत 600 से 950 किग्रा तक दुग्ध उत्पादन करती है।

ग्वालो गाय मध्य प्रदेश बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, छत्तीसगढ़ के दुर्ग एवं राजनगांव तथा महाराष्ट्र के वर्धा एवं नागपुर जनपदों में पायी जाती है। यह एक तेजी से घूमने वाली नस्ल है जोकि पहाड़ी क्षेत्रों में त्वरित परिवहन के लिये काफी उपयुक्त है। इस नस्ल की गाय का प्रति ब्यांत

605 से लेकर 725 किग्रा तक दुग्ध उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश राज्य की गायों की चार प्रमुख नस्लों के अलावा एक अन्य स्थानीय स्वदेशी नस्ल भी पाई जाती है। जिसकी कुछ वर्षों पूर्व ही बावरी नस्ल की गाय के रूप में पहचान की गई है। मध्य प्रदेश के चंबल संभाग के श्योपुर एवं मुरैना जिले के कुछ विकास खण्डों में एक अनोखी पशु आबादी दिखाई देती है जिसे स्थानीय लोग 'बावरी' के रूप में पहचानते हैं। श्योपुर जिले के विजयपुर, करालहल तथा मुरैना जिले के सबलगाढ़, कैलारस एवं जौरा विकास खण्डों में यह पशु आबादी कहीं ज्यादा तो कहीं कम दिखाई देती है। स्थानीय रूप से 'बावरी' (जिसे गरी के नाम से भी जाना जाता है) के रूप में जाना पहचाना जाता है। बताया जाता है कि इस गाय के दूध का खोआ बहुत ही उम्दा किस्म का बनकर तैयार होता है।

वहीं भैंस की बात करें तो राज्य की एकमात्र नस्ल भदावरी को माना जा सकता है जोकि उत्तर प्रदेश के साथ ही मध्य प्रदेश के कुछ जनपदों की स्थानीय नस्ल है। इस नस्ल की उत्पत्ति भदावर क्षेत्र की मानी जाती है जोकि आगरा एवं इटावा जनपदों के अंतर्गत पुरातन भदावर राज्य कहलाता था जोकि उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा एवं भिंड (म.प्र.) जनपदों के अंतर्गत आता है। इसी नस्ल की भैंस यमुना और चम्बल नदी के किनारे पाये जाने वाले बीहड़ों में प्रमुखता से पाई जाती थी। इसी के चलते भदावरी नस्ल भिंड, मुरैना के बीहड़ों से लेकर ग्वालियर जनपद के कुछ क्षेत्रों में भी पायी जाती है, लेकिन इन जनपदों में भी भदावरी नस्ल की भैंस अब बहुत कम दिखाई देती है। चंबल के बीहड़ों में भी स्थानीय पशुपालकों के यहां इस नस्ल की भैंस दिखाई नहीं देती जबकि बीहड़ों के दूरदराज के गांवों और वहां की भौगोलिक परिस्थितियों में इस नस्ल की भैंस बहुत ही अनुकूल मानी जाती रही है।

## मजबूत बुनियाद पर आत्म-निर्भरता की ओर अग्रसर प्रदेश की ग्रामीण महिलाएं

भोपाल। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा वर्ष 2012 से प्रदेश में ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण के लिये स्व-सहायता समूह बनाकर उनके संस्थागत विकास तथा आजीविका के संवहनीय अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

मिशन द्वारा प्रदेश में अब-तक 45 हजार 135 ग्रामों में 3 लाख 36 हजार 521 स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है। इन समूहों से 38 लाख 31 हजार परिवारों को जोड़ा जा चुका है।

**वित्तीय सहयोग:** समूहों को मिशन द्वारा चक्रिय निधि, सामुदायिक निवेश निधि, आपदा कोष तथा बैंक लिंकेज के रूप में वित्तीय सहयोग किया जा रहा है। इस राशि से उनकी छोटी-बड़ी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, जिससे वे साहूकारों के कर्जजाल से बच जाते हैं। प्रदेश में समूहों को विभिन्न आजीविका गतिविधियों के संचालन के लिये बैंक ऋण वितरण का लक्ष्य विगत दो वर्षों में कई गुना बढ़ाते हुए इस वर्ष में 2550 करोड़ रुपये किया गया है। समूहों को सस्ती ब्याज दरों पर पूंजी उपलब्ध कराने के साथ अलग से ब्याज अनुदान भी दिया जा रहा है।

**व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में अवसर:** राज्य सरकार ने महिला स्व-सहायता समूहों के कार्यों का दायरा बढ़ाते हुए पोषण आहार संयंत्रों के संचालन का बहुत बड़ा काम भी समूहों को देकर वृहद कारोबारों को संचालित करने का अनुभव समूहों की महिलाओं को दिया है। नित नये क्षेत्रों जैसे दीदी कैफे संचालन, उचित मूल्य की शासकीय दुकानों का संचालन, स्कूल गणवेश सिलाई, फसल क्रय के लिये उपार्जन केन्द्रों का संचालन, गौशाला संचालन, चारागाह विकास, अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट संचालन, ग्रामीण क्षेत्रों में नल-जल योजनाओं का संचालन, विद्युत बिल वितरण कार्य, सड़कों का संधारण, लघु वनोपज संग्रहण, शासकीय निर्माण कार्यों में लगने वाली ईंट आदि सामग्री के निमाड़ एवं सप्लाय में प्राथमिकता देते हुये स्व-सहायता समूहों को हर स्तर पर सहयोग किया जा रहा है। समूहों की सदस्य महिलाओं द्वारा रुचि अनुसार परंपरागत आय के साधन कृषि-पशुपालन के साथ अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिये सिलाई, दुकान,

साबुन, अगरबत्ती निर्माण आदि सहित 103 प्रकार की लघु उद्यम गतिविधियों की जा रही हैं।

**उत्पादों के क्रय-विक्रय में सहयोग:** समूहों के उत्पादों को बेचने के लिये आजीविका रूरल मार्ट जिला स्तर पर नाबाई के सहयोग से स्थापित किये गये हैं। आजीविका मार्ट पोर्टल के माध्यम से भी उत्पादों के क्रय-विक्रय में सहयोग किया जा रहा है। समूहों के उपयोग के लिये ब्लॉक स्तर पर आजीविका भवन निमाड़ किया गया है। समूहों की बैठकों तथा आजीविका गतिविधि केन्द्र और प्रशिक्षण केन्द्र बनाने के लिये बड़ी संख्या में शासकीय भवन समूहों को आवंटित किये गये हैं।

**निरंतर प्रशिक्षण:** मिशन द्वारा दिये जा रहे लगातार प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय सहयोग एवं मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि समूह सदस्यों के अन्दर गरीबी से उबरने की दृढ़ इच्छा-शक्ति उत्पन्न हुई। आज प्रदेश में समूहों से जुड़े 13 लाख 37 हजार से अधिक परिवार कृषि एवं पशुपालन आधारित आजीविका गतिविधियों से जुड़े और 5 लाख 5 हजार से अधिक परिवार गैर कृषि आधारित लघु उद्यम आजीविका गतिविधियों से जुड़कर काम कर रहे हैं।

**महिलाओं को मिल रही है नई पहचान:** पहले ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन परिवारों में महिलाओं को आय मूलक गतिविधियां करने के अवसर नहीं मिलते थे, उनका जीवन केवल चूल्हे-चौंके और घर की चार दीवारी तक ही सीमित रह जाता था। घर के संचालन, आय-व्यय, क्रय-विक्रय आदि सहित अन्य मुद्दों पर निर्णय में पुरुषों का एकाधिकार था। मिशन के समूहों से जुड़कर महिलाओं को जो अवसर मिला, उससे उन्होंने अपनी काबिलियत सिद्ध कर अपनी अलग पहचान बनाई। अब समूह सदस्य महिलाएं अपने परिवार के साथ गाँव एवं सामुदायिक विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय देती हैं। उनमें आई जागरूकता से न केवल घर में बल्कि गाँव और क्षेत्र में भी उनके सम्मान में बढ़ोतरी हुई है।

## आत्मनिर्भरता: विकल्प अथवा अवसर

राम गोपाल सोनी

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां के ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी मुख्यतः कृषि आधारित आजीविका पर निर्भर है जो कि भारत की जनसंख्या का 60 प्रतिशत है। इनमें से लगभग 82 प्रतिशत छोटे एवं सीमांत किसान हैं। आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद का 20.19 प्रतिशत योगदान प्रतिशत का रहा है। सापेक्षिक दृष्टिकोण से यह हिस्सेदारी फिर भी कम है।

हालांकि कृषि सुधार हेतु अनेक योजनाएं लागू की जा रही हैं, परंतु जमीनी स्तर तक पहुंचने में प्रायः सिमट जाती हैं। इसका प्रमुख कारण जागरूकता का अभाव एवं पारंपरिक कृषि प्रणाली के प्रति उदासीनता है। संसाधनों के अभाव में भी हमारे पूर्वज कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर थे, क्योंकि वे प्राकृतिक पद्धति आधारित खेती करते थे।

वर्तमान परिदृश्य में किसान के पास अधिक परिश्रम करने की क्षमता है, परंतु उनके पारिश्रमिक का निधाज्जण कृषि उत्पाद की बिक्री, व्यापारियों एवं खाद्य वितरण प्रणाली पर ही निर्भर है। यह निर्भरता ही कृषि की आय को सुनिश्चित नहीं होने देती है। चूंकि अधिकांश किसान सीमांत श्रेणी में आते हैं। कम भू-भाग होने की वजह से इनके कृषि उत्पादन भी सीमित ही होते हैं, इसलिए कृषि क्षेत्र में



आत्मनिर्भरता एक अति आवश्यक पहलू बनकर उभर रहा है। कोविड ने भी कृषि क्षेत्र को अत्यंत प्रभावित किया है। संसाधनों के अतिरिक्त खर्च, बाजारों की बंदी, लॉकडाउन इत्यादि समस्याओं के वजह से लागत एवं आय दोनों ही असंतुलित रहे हैं। यद्यपि लोगों का रुझान अब प्राकृतिक संसाधनों की तरफ बढ़ रहा है। सीमांत किसान को यही रुझान समझने की जरूरत है। प्राकृतिक कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग किसान की आय वृद्धि का न सिर्फ विकल्प है, अपितु अवसर भी है। पूर्ण रूप से आत्मनिर्भरता एक अत्यंत जटिल व विवादास्पद विषय है। परंतु जनसंख्या वृद्धि एवं बढ़ती बेरोजगारी के प्रतिस्पर्धात्मक दौर में आत्मनिर्भरता ही एकमात्र विकल्प है। कृषि क्षेत्र में ही लागत मूल्य की आशातीत वृद्धि उदाहरण स्वरूप बीज मूल्य, उर्वरक, जुताई, सिंचाई एवं अन्य कृषि संबंधी कार्यों के निर्वहन में निरंतर आर्थिक बढ़ोतरी किसान की जेब ढीली करती जा रही है।

# कम लागत में ज्यादा आमदनी देने वाली देशी फसल, सालभर शरीर में नहीं होने देती है फास्फोरस की कमी विंध्य और बालाघाट में हो रही सूरन की खेती

संवाददाता, सैवा/बालाघाट

कहा जाता है कि सूरन की खेती देश में सबसे अधिक छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब सहित अन्य राज्यों में होती है। लेकिन अब शिवराज में भी किसानों का रुझान बढ़ गया है। मप्र में सबसे अधिक बालाघाट में सूरन की खेती हो रही है। हालांकि अब रीवा जिले की तहसील मऊगंज के प्रगतिशील किसान अनिल कुमार मिश्रा ने भी इस वर्ष से इसकी खेती शुरू कर दी है। उन्होंने इस साल करीब तीन सौ पौधे लगए थे। जिसकी अभी खुदाई नहीं की गई है। दरअसल, मप्र में सूरन यानी जिमीकंद की खेती लोगों के मकान की बाड़ी तक ही सीमित रहती थी, लेकिन

अब कटंगी तहसील के तीन गांवों में इसकी खेती करने छोटे किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। सूरन कम लागत में ज्यादा आमदनी देने वाली फसल है, जिससे छोटे किसानों की आर्थिक हालत में सुधार हो सकेगा और उन्हें महानगरों में मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी।

**नौ माह में तैयार** - सूरन की खेती करने फरवरी से जून माह तक बोवनी की जाती है। फसल नौ से दस माह में तैयार हो जाती है। यह नकदी फसल है और बाजार में 40-50 रुपए किलो से अधिक दाम पर बिकती है। अभी मप्र की राजधानी भोपाल में इसकी कीमत 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा है।



यह है खास

- » एक हेक्टेयर में दो सौ से ढाई सौ क्विंटल उत्पादन।
- » कम मेहनत और बारिश के पानी से हो जाती है खेती।
- » सब्जी के अलावा मुरब्बा भी बनता है, त्योहारों पर अधिक मांग।
- » फसल को मवेशी नहीं पहुंचाते नुकसान।
- » वजन कम करने, कैंसर, बवासीर आदि बीमारियों में फायदेमंद।

**लागत और फायदा**

विंध्य के प्रगतिशील किसान अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि जहां सूरन की खेती की जाती है कि वहां उतम जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। खेती योग्य भूमि तैयार करने के लिए दो जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और तीन-चार जुताई देशी हल से अच्छी तरह करके मिट्टी को भुरभुरी, मुलायम और समतल कर लेना चाहिए। सूरन का उत्पादन लागत प्रति हेक्टेयर 3 लाख 36 हजार 40 रुपए और आय 12 लाख है। हालांकि मैंने तो अभी इसकी छोटे से रकबे में शुरुआत की है।

**दीपावली के दिन सूरन की सब्जी**

दीपावली के दिन घरों में सूरन की सब्जी बनती है। आजकल तो बाजार में हाईब्रीड सूरन आ गया है। कभी-2 देशी वाला सूरन भी मिल जाता है। सब्जियों में सूरन ही एक ऐसी सब्जी है जिसमें फास्फोरस अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। ऐसी मान्यता है और अब तो मेडिकल साइंस ने भी मान लिया है कि एक दिन यदि हम देशी सूरन की सब्जी खा लें तो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पूरे साल फास्फोरस की कमी नहीं होगी।

इंदौर के छह किसानों को 112 लाख की मदद मिली

# जिले में आलू-चिप्स उद्योग को मिल रहा नया स्वरूप

संवाददाता, इंदौर

इंदौर जिले में आलू-चिप्स उद्योग को मिल रहा है नया स्वरूप। एक फसल एक उत्पाद योजना के अंतर्गत इंदौर जिले में आलू फसल का चयन किया गया है। आलू तथा इससे बने उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए इंदौर जिले में किए जा रहे विशेष प्रयासों के नतीजे सामने आ रहे हैं। आलू प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए किसान आगे आ रहे हैं।

इन किसानों को प्रधानमंत्री सूक्ष्म, खाद्य, उद्योग, उन्नयन योजना के तहत ऋण एवं अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिले में अभी तक 6 किसानों को 112 लाख रुपए से अधिक की मदद स्वीकृत की गई है। इनमें से तीन किसानों ने अपनी इकाइयां स्थापित कर ली है। शेष तीन किसानों द्वारा अपनी इकाइयों का शीघ्र ही भूमिपूजन किया जाने वाला है।

उप संचालक उद्यानिकी टीआर वास्करले ने बताया कि इंदौर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश का प्रमुख आलू उत्पादक जिला है। यहां उत्पादित होने वाली आलू की अनेक विशेषताएं हैं। इसलिए इंदौर जिले में एक जिला एक उत्पाद के तहत आलू का चयन किया गया है। कलेक्टर मनीष सिंह के मार्गदर्शन में इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्य प्रारंभ किए गए हैं। वास्करले ने बताया कि जिले में 25 से 35 लाख तक का ऋण किसानों को मुहैया कराया जा रहा है। इसमें अधिकतम 10 लाख तक की सब्सिडी दी जा रही है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना अंतर्गत 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंकड अनुदान पर आलू फसल आधारित नवीन सूक्ष्म उद्योग लगाने के लिए विकासखंडवार प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। कार्यशाला / प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वैज्ञानिकों के माध्यम से तकनीकी मार्गदर्शन और फूड सेफ्टी कानून, ब्रांडिंग आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है।



**किसानों की समितियां भी गठित**

इंदौर जिले में आलू उत्पादक किसानों की समितियों का गठन भी हो रहा है। योजना का क्रियान्वयन उद्यानिकी, उद्योग, सहकारिता, कृषि, नाबाई, आदि के समन्वित प्रयासों के साथ किया जा रहा है। इसके तहत जिले के 6 किसानों जिनमें कोदरिया के मंदेश सूले, प्रीतम सांखले तथा विकास कैलोतरा, पेडमी के राजवीर सिंह डबर, राजधरा के मनोहर पाटीदार तथा कोदरिया के अशोक कापड़े शामिल हैं। इन्हें लगभग 112 लाख की वित्तीय मदद दी गई है। इनमें से तीन किसानों ने 73 लाख निवेश कर इकाइयां स्थापित कर ली है। शेष किसानों द्वारा इकाइयों की स्थापना का कार्य शुरू किया जा रहा है।

**इंदौर का शुगर फ्री आलू**

इंदौर के शुगर फ्री आलू की मांग तेजी से बढ़ रही है। यहां से आलू देश के अन्य राज्यों के साथ-साथ विदेशों में भी भेजा जाता है। इस मांग को देखते हुए किसान अब बड़ी संख्या में आलू की खेती के लिए आगे आ रहे हैं। जिले में महु क्षेत्र के ग्राम गवली पलासिया, जामली, बिचौली, कोदरिया, बड़गोंदा, हरसोला, दतोदा, हासलपुर, मेमदी, कुवाली, मानपुर, टीही, राऊ, रंगवासा, कैलोद और मेण में प्रमुख रूप से आलू की खेती की जा रही है। इंदौर की शुगर फ्री आलू से बनी हुई चिप्स तलने में लाल नहीं होती है, वह तलने के बाद सफेद ही रहती है। जिले में हर वर्ष आलू फसल 45 हजार हेक्टेयर में बोई जा रही है। विगत वर्षों में प्रतिवर्ष उत्पादन लगभग 11 से 12 लाख मीट्रिक टन हुआ था। उत्पादकता 25-50 प्रति हेक्टेयर मीट्रिक टन रही थी। जिले में औसत उत्पादकता 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलती है। किसान अधिकतम उत्पादन 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त करते हैं।

**गुणों से भरपूर आलू और खाद्य सामग्री**

आलू अनेक गुणों से भरपूर है। आलू में अनेक स्वास्थ्यवर्धक तत्व पाए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से विटामिन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज, फॉस्फोरस आदि होते हैं। इसके अनेक औषधीय गुण भी हैं। त्वचा के लिए भी बेहद फायदेमंद है। माना जाता है कि अगर चमड़ी जल जाये तो आलू काटकर उसे लगायें तो तुरंत राहत महसूस होती है। इंदौर में उत्पादित होने वाली आलू की देश-दुनिया में बड़ी मांग है। इससे अनेक स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ बनते हैं। इंदौर में आलू से बनने वाले चिप्स, पापड़, समोसे, कचौड़ी, आलू बड़े, टिक्की, फ्रेंचफ्राइस आदि की विशेष पहचान है। इंदौर में उक्त खाद्य पदार्थ बनाने के लिए वर्तमान में अनेक प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा इंदौर में कारखाने स्थापित किए गए हैं। छोटे स्तर पर भी बड़ी संख्या में कारखाने चल रहे हैं। आलू एक ऐसी खाद्य वस्तु है जिसे प्रायः किसी भी सब्जी में मिलाकर उसका स्वाद बढ़ाया जा सकता है।

# बकरी पालनों को खुशखबरी, अब दूध खरीदेगी सरकार

संवाददाता, भोपाल

बकरी पालन को किसानों और पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने का एक मुख्य स्रोत माना जाता है। बकरी पालन का व्यवसाय कम लागत और सामान्य रख-रखाव में आय का अच्छा साधन माना गया है।



इसके चलते 15 नवंबर से एमपी स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जनजातीय क्षेत्रों में बकरी के दूध का संकलन शुरू करेगा। इस पहल से आदिवासी लोगों की आमदनी में बढ़ोत्तरी होगी। प्रबंध संचालक शमीमुद्दीन द्वारा जानकारी दी गई है कि फेडरेशन संचालित दुग्ध संघों द्वारा रोजाना लगभग साढ़े तीन करोड़ की राशि का हस्तांतरण शहरी अर्थ-व्यवस्था से ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में किया जा रहा है। वहीं, दुग्ध संघों द्वारा 7 हजार से अधिक दुग्ध सहकारी समितियों के 2-5 लाख सदस्यों के माध्यम से रोजाना 10 लाख लीटर दूध का संकलन किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पशुपालन और मत्स्य पालन, दोनों ही क्षेत्रों से आमदनी में इजाफा हुआ है। कोरोना व लॉकडाउन के दौरान भी कई रोजगार प्रभावित हुए थे, लेकिन सभी 6 दुग्ध संघों द्वारा दुग्ध उत्पादक किसानों से 2 करोड़ 54 लाख लीटर दूध अतिरिक्त रूप से खरीदा गया। इसके लिए दुग्ध उत्पादकों को 94 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान हुआ। इसके साथ ही उन्हें एक महत्वपूर्ण आर्थिक संबल मिला।

**नए उत्पादों का विकास**

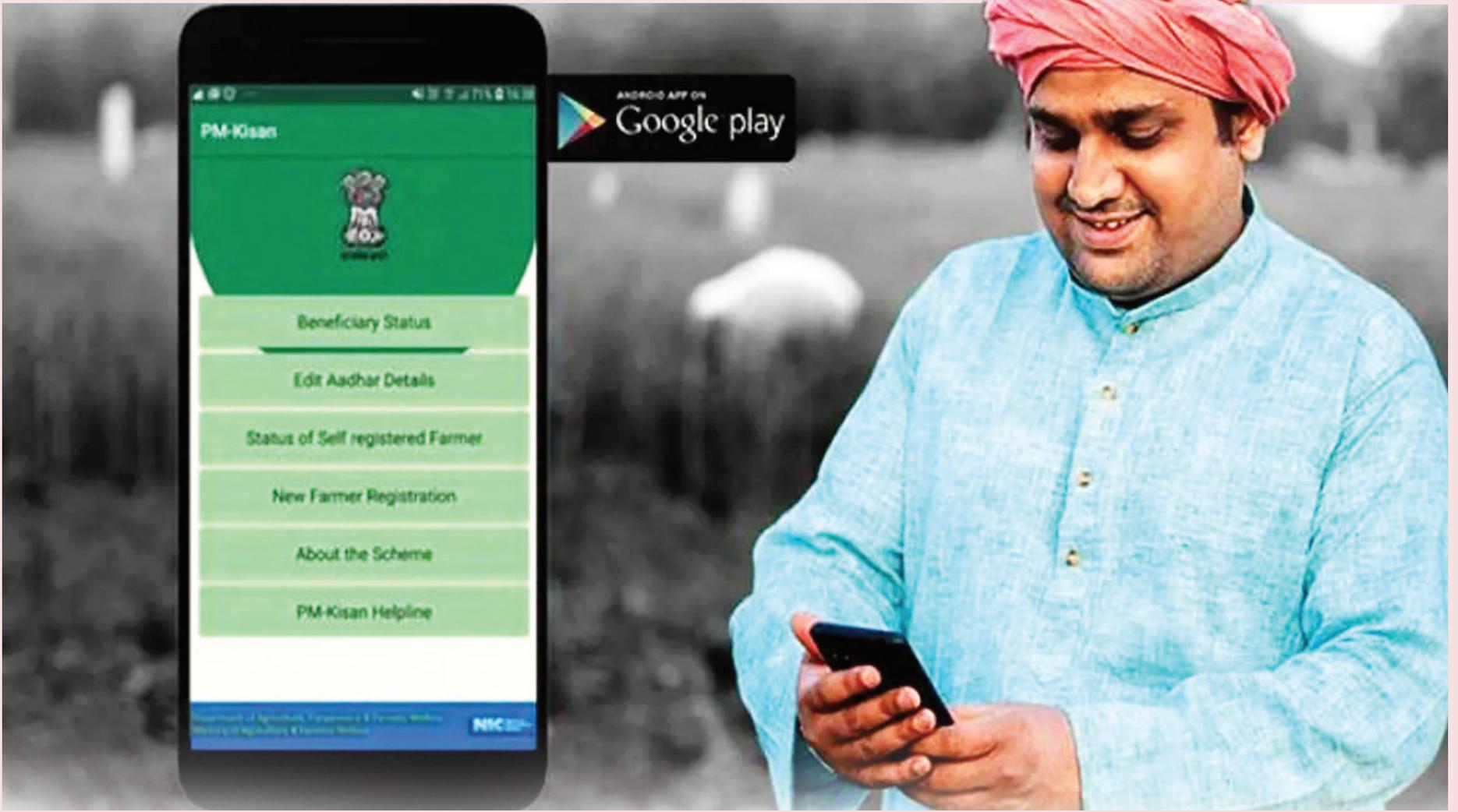
दुग्ध संघों द्वारा नवीन उत्पादों का निर्माण का किया जा रहा है। इंदौर में आइस्क्रीम और जबलपुर में पनीर संयंत्र की स्थापना हुई, तो वहीं सागर तथा खंडवा में नवीन दुग्ध प्र-संस्करण स्थापित भी हुए। इंदौर में दुग्ध चूर्ण निर्माण में आत्म-निर्भरता के मद्देनजर 30 मीट्रिक टन क्षमता के संयंत्र की स्थापना की जा रही है। इतना ही नहीं, दूध, घी, दही, पेड़े, मट्ठा, श्रीखंड, पनीर, छेना रबड़ी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, आइस्क्रीम, शुगर-फ्री पेड़ा, मिल्क केक, मीठा दही, पलेवर्ड मिल्क आदि गुणवत्ता के चलते काफी लोकप्रिय किए।

**दूध में नहीं हो सकेगी मिलावट**

इसके साथ ही मध्य प्रदेश में दूध में मिलावट भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि दुग्ध संकलन करने वाले टैकरों में डिजिटल और क्लीकल ट्रेकिंग सिस्टम लगा है। दुग्ध संघों में वेब आधारित ईआरपी सॉफ्टवेयर है, ताकि दूध संकलन से दूध वितरण तक की संपूर्ण प्रक्रिया एकीकृत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संचालित हो सके।

**दुग्ध उत्पादकों को सुविधाएं**

जानकारी के लिए बता दें कि दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध उत्पादकों को विक्रय के अतिरिक्त कई सुविधाएं दी जा रही हैं। इनमें उचित मूल्य पर पशु आहार, चारा बीज, पशु नस्ल सुधार, पशु प्रबंधन प्रशिक्षण, किसान क्रेडिट कार्ड, पशुओं की डी-वार्मिंग, बच्चों के लिए पुरस्कार योजना और बीमा योजना आदि शामिल हैं। इन सभी सुविधाओं का आसानी का लाभ दिया जा रहा है।



भोपाल। भारत एक कृषि प्रधान देश है। खेती करने के बदलते तरीकों में किसानों की हर मामले में भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है। सरकार तकनीक के सहारे उन्नत खेती को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए सभी प्रयास कर रही है। डिजिटल इंडिया के तहत खेती-बाड़ी एवं उनसे जुड़ी तमाम योजनाओं, परियोजनाओं एवं सूचनाओं को किसानों तक पहुंचाना भी सरकार की उसी प्राथमिकता का हिस्सा है। डिजिटल इंडिया के इस दौर में किसानों के लिए भी कई ऐप्स हैं, जो खेती करने में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं तो आइए हम बताते हैं उन सभी ऐप के बारे में जो आपकी खेती को बनाएं और आसान ये जानने के लिए पढ़िए **जागत गांव हमार...**

# अन्नदाता को ऐप बनाएंगे आत्मनिर्भर



किसानों के लिए खेती में बेहद मददगार बन रहे ऐप्स

## किसान सुविधा

पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया किसान सुविधा ऐप के माध्यम से मौसम की जानकारी दी जाती है। यह ऐप उपयोग करने के बहुत सरल है। इस ऐप में आज के मौसम के साथ आने वाले 5 दिनों के मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है। साथ ही आस-पास के बाजार में फसलों की कीमतों के बारे में सूचना मिलती है। यह ऐप कई भाषाओं में मौजूद है।

## इफको किसान कृषि

इफको का किसान ऐप 2015 में लॉन्च किया गया था। इस ऐप में किसान को खेती को लेकर कुछ टिप्स, मौसम, बाजार की कीमतों जैसी कई जरूरी जानकारियां मिलती हैं। इसके साथ ही इस ऐप के हेल्पलाइन नंबर के जरिए किसान सेवा सेंटर को कॉल भी किया जा सकता है।

## आरएमएल किसान कृषि मित्र

ऐप के जरिए किसान आसपास के बाजार में उत्पादों के दाम के अलावा खाद-बीज की कीमतों के बारे में भी जान सकते हैं। साथ ही यह ऐप किसानों से जुड़ी सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी देता है।

ऐप में किसान देश के 17 राज्यों के 50,000 गांवों की 3500 लोकेशन के मौसम के बारे में पता कर सकते हैं। 1300 मॉडलों और 450 प्रकार की फसलों से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

## पूसा कृषि

इस ऐप को 2016 में कृषि मंत्री ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि रिसर्च इंस्टिट्यूट के द्वारा बनाई गई नई तकनीकों के बारे में किसानों को बताना है। इसके अलावा भी इस ऐप में किसानों और खेती से जुड़ी कई काम की जानकारियां होती हैं।

## दामिनी एप

एक लाइटनिंग अलर्ट ऐप है और वह एक वेदर ऐप है। ये ऐप सभी बिजली की गतिविधियों की निगरानी करता है, जो विशेष रूप से पूरे भारत में हो रही हैं। दामिनी ऐप बिजली, वज्रपात और उनका की सटीक जानकारी 30 मिनट पूर्व ही दे देगा। इसके लिए ऊष्णदेशीय मौसम विज्ञान के वैज्ञानिकों ने देश के विभिन्न हिस्सों में करीब 48 सेंसर के साथ एक लाइटनिंग लोकेशन नेटवर्क स्थापित किया है।

## मौसम ऐप

मौसम ऐप एक ऐसा ऐप है, जो आपके क्षेत्र के लिए मौसम की स्थिति की रिपोर्ट देती है। भारत के कई मौसम मानचित्रों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की मौसम की जानकारी लाती है। मौसम ऐप भारत मौसम विज्ञान विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार का एक मोबाइल ऐप है।

## मेघदूत ऐप

भू-विज्ञान, विज्ञान और तकनीक मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मेघदूत ऐप को लॉन्च किया। मेघदूत ऐप की मदद से किसान तापमान, वर्षा, नमी और वायु की तीव्रता और दिशा के बारे में जान सकते हैं। किसान मौसम संबंधी यह जानकारी लेकर फसल और मवेशियों की बेहतर तरीके से देखभाल कर सकते हैं। मेघदूत मोबाइल ऐप को भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय ऊष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने मिलकर लॉन्च किया है।

## आत्मनिर्भर कृषि ऐप

केंद्र सरकार ने 29 जून 2021 को किसानों को खेती संबंधी जानकारी और मौसम की पहले से सूचना उपलब्ध कराने के लिए आत्मनिर्भर कृषि ऐप की शुरुआत की है। राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानमित्र पर विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा किसानों के लिए प्रासंगिक जानकारी का खजाना अब आत्मनिर्भर कृषि ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। यह एप एंड्रॉइड और विंडोज संस्करणों में किसानों, स्टार्टअप, कृषि विज्ञान केंद्रों, स्वयं सहायता समूहों और गैर सरकारी संगठनों के लिए 12 भाषाओं में मुफ्त में उपलब्ध होगी।

## किसान रथ ऐप

किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने किसान रथ ऐप लॉन्च किया। किसान रथ ऐप के जरिए किसान और व्यापारी आसानी से फसलों की खरीद और बिक्री कर सकते हैं। कृषि उत्पादों के परिवहन में सुगमता लाने के उद्देश्य से किसान रथ मोबाइल एप लांच किया। किसान रथ ऐप के जरिए किसान और व्यापारी आसानी से फसलों की खरीद और बिक्री कर सकते हैं। किसान रथ अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु भाषा में उपलब्ध है।

## किसान-सारथी मोबाइल ऐप

कृषि क्षेत्र को आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस करने के साथ उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए किसान-सारथी मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी और कृषि मंत्रालय की यह संयुक्त पहल किसानों को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगी। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसानों को फसलों की बोआई से लेकर उपज की बिक्री तक की जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। किसान सारथी के माध्यम से किसान सीधे विषय विशेष के विज्ञानियों से सीधी बात भी कर सकता है। देश के 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र इसके नेटवर्क से जुड़ गए हैं।



## ई नाम मोबाइल ऐप

ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। आसान शब्दों में ये किसान भाइयों मौजूदा मंडियों के नेटवर्क को एक जगह लाकर एकीकृत राष्ट्रीय बाजार मुहैया कराता है। साथ ही व्यापारियों को कहीं से भी बैठकर किसानों के फसलों को खरीदने का सुविधा प्रदान करता है। किसान घर बैठे अपने उत्पाद के बाजार मूल्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकेंगे तथा बाजार में पंजीयन भी करा सकेंगे। ई-नाम वेबसाइट हिन्दी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगू, बंगला और उड़िया भाषा में उपलब्ध है। ई-नाम पोर्टल में एमआईएस डैशबोर्ड, व्यापारियों को भी एप द्वारा भुगतान की सुविधा, मोबाइल भुगतान की सुविधा आदि को शामिल किया गया है।

## पशु पोषण ऐप

इस ऐप को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) ने विकसित किया है। इसमें पशुओं के प्रोफाइल, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध में वसा और पशुओं को क्या आहार सामग्री दी जाए इस बारे में खास जानकारी दी जाती है। इस ऐप को भी पशुपालक अपने फोन पर डाउनलोड करके आहार संतुलन कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप में हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। पशुपालकों को सिर्फ वेबसाइट पर जा कर अपना पंजीकरण करना है, फिर अपने इंद्राइट फोन पर अपने पशु का पंजीकरण करके उनका आहार संतुलन करना है पंजीकरण के लिए अपने गायों और भैंसों को 12 नंबर का विशिष्ट टैग/ कड़ी लगाना जरूरी है।

## ई-फिश मार्केट ऐप

ई-फिश मार्केट ऐप को एक्वा ब्लू ग्लोबल एक्वाकल्चर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राज्य के मत्स्य विभाग की मदद से तैयार किया गया है। इसके जरिए जलीय कृषि के लिए वन-स्टॉप समाधान, खरीदारों और विक्रेताओं, दोनों को मछली, जलीय कृषि उपकरण और दवा, मछली फीड और मछली बीज ऑनलाइन ऑर्डर करने और बेचने में मदद मिल पाएगी। इसके अलावा ऐप पर मीठे पानी और समुद्री जल में जमी हुई मछली, सूखी मछली, मछली का अचार और प्रसंस्कृत मछली उत्पाद भी उपलब्ध होंगे। इस ऐप के जरिए मछली पालन करने वाले लोगों को उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही बिचौलियों का सफाया होगा। यहां करीब डेढ़ करोड़ लोग इस व्यवसाय से जुड़कर अपनी आजीविका चला रहे हैं।

## कृष-ई ऐप

कृष-ई महिंद्रा का एक नया बिजनेस वटिज्कल है जो टेक्नोलॉजी संचालित सेवाएं प्रदान करता है, जो किसानों के लिए उन्नतिशील, सस्ती और सुलभ हैं। कृष-ई का लक्ष्य पूरे फसल चक्र में भौतिक सेवाओं के साथ-साथ डिजिटल सेवाओं के जरिये कृषि आय में वृद्धि करना है। कृष-ई ऐप वैज्ञानिक, खेतों के लिए मान्यता प्राप्त और फसल संबंधी व्यक्तिगत परामर्श प्रदान करता है जो ऐसे फॉर्मेट में प्रस्तुत किया जाता है, जो किसानों के लिए समझने और अपनाने में आसान हो।

## मत्स्य सेतु ऐप

मछली पालन को लेकर किसानों तक सही जानकारी पहुंच सके इसके लिए केंद्र सरकार की तरफसे हाल में ही मत्स्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिये मछलियों की अलग-अलग प्रजातियों के बारे में जानने के लिए, ऑनलाइन सेल्फ-लर्निंग मॉड्यूल उपलब्ध कराए जाएंगे। इन एप्स को अपने फोन के गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको बहुत लाभदायी साबित होंगे।

## केले की खेती के लिए विशेष ऐप

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र ने सेंटर फॉर डेवेलपमेंट ऑफ एडवांस कंयूटिंग, हैदराबाद के साथ मिलकर केले की खेती करने वाले किसानों के लिए एक ऐप बनाया है। इस मोबाइल ऐप का नाम बनाना प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी (केला-उत्पादन प्रोद्योगिकी) है। यह ऐप फिलहाल हिंदी, अंग्रेजी और तमिल भाषा में है। किसान इसे गूगल प्ले स्टोर से अपने स्मार्ट मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए किसानों को जलवायु संबंधी आवश्यक जानकारी, मृदा संबंधी आवश्यकताएं, पौध रोपण सामग्री, रोपाई, जल प्रबंधन, पोषक तत्व प्रबंध, उर्वरक समायोजन समीकरण, केले की खेती संबंधित अन्य अंतः क्रियाएं, फलों का परिपक्व होना व फल गुच्छों की कटाई और फलोत्पादन समेत कई अन्य तरह की जानकारी मिलेंगी।

## सीएचसी-फॉर्म मशीनरी ऐप

छोटी जोत के किसान अक्सर महंगे कृषि उपकरण खरीद नहीं पाते। यही कारण है कि वे कई बार खेतों में जरूरी काम नहीं करा पाते। किसानों को ऐसी समस्याओं से उबारने के लिए ही है सीएचसी-फार्म मशीनरी ऐप। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के इस ऐप पर रजिस्टर के बाद किसान घर बैठे किराए पर सभी कृषि उपकरण मंगा सकते हैं। किसान इस ऐप के माध्यम से बड़े आसानी से ट्रैक्टर और दूसरे कृषि मशीनरी किराए पर मंगा सकते हैं।

## वीड मैनेजर ऐप

खरपतवार अनुसंधान निदेशालय ने वीड मैनेजर ऐप भी विकसित किया है, जिसमें हर तरह के खरपतवार की जानकारी है। कौन-कौन से

खरपतवार होते हैं, किस फसल में कौन से खरपतवार होते हैं। कुछ चौड़ी पत्ती के होते हैं, कुछ सकरी पत्ती के, जैसे कि कुछ खरपतवार मौसमी होते हैं, कुछ एक वर्षीय होते हैं और कुछ तो बहुवर्षीय होते हैं। जैसे कि कांस, दूब बहुवर्षीय होती है, गुंदला, नागरमोथा, मोथा वार्षिक होते हैं, और अकरी, जंगली प्याज, बथुआ मौसमी होते हैं। वीड मैनेजर की मदद से किसान हर एक खरपतवार की पहचान सकता है। साथ ही रसायनिक और यांत्रिक विधियों से इनके नियंत्रण के बारे में जानकारी दी गई है। किसानों के साथ ही स्टूडेंट्स, एनजीओ, वैज्ञानिक और कृषि विभाग के अधिकारी भी इससे जानकारी ले सकते हैं।

## क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट-एगी मोबाइल ऐप

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, सरकार द्वारा विकसित ये ऐप किसानों को फसल काटने संबंधित नए प्रयोगों के बारे में बताता है। इसकी खास बात है कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में काम करता है। केवल इस ऐप को डाउनलोड करने और पंजीकरण के लिए इंटरनेट की आवश्यकता है। उसके बाद बिना इंटरनेट के भी इस ऐप की मदद ली जा सकती है।

## सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम ऐप

मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम ऐप के माध्यम से किसान भाई अपनी भूमि के स्वास्थ्य की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा ये भूमि की उर्वरकता में कुछ कमी होने पर मिट्टी में संशोधन की सलाह भी दी जाती है। साथ ही पौधों को कौन से पोषण तत्वों की जरूरत है इस बारे में इस पर जानकारी मौजूद है।

## मुवन हेलस्टॉर्म ऐप

केंद्र सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इस ऐप को विकसित किया है। इस ऐप के माध्यम से ओलावृष्टि से फसल को जो नुकसान हुआ है, वह आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस ऐप में रजिस्ट्रेशन कर ओलावृष्टि से नुकसान फसलों की तस्वीरें अपलोड करनी होती हैं, जिसके बाद कृषि अधिकारी आपके फसल का जायजा लेंगे और आपको मुआवजा की रकम मुहैया करा दी जाएगी।

## हर्बिसाइड कैलकुलेटर ऐप

खरपतवार अनुसंधान निदेशालय, जबलपुर ने हर्बिसाइड कैलकुलेटर ऐप बनाया है, जिसके जरिए किसानों को हर बात की सटीक जानकारी मिलती है। यहां पर वैज्ञानिक किसानों को खरपतवार प्रबंधन की जानकारी देते हैं, पूरे देश में निदेशालय के 23 केंद्र हैं। किसान इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।

## इस ऐप की खास बातें

- » रबी, खरीफ और जायद की तमाम फसलों को इसमें जोड़ा गया है
- » कौन सा हर्बिसाइड (शाशनाशक) आप उपयोग करना चाहते हैं, इसका भी ऑप्शन इसमें मौजूद है
- » जमीन के हिसाब से किसानों को कितना हर्बिसाइड उपयोग करना चाहिए इस बारे में भी जानकारी देगा ये ऐप
- » फसलों के हिसाब से खरपतवार के प्रबंधन के लिए कितने डोज हर्बिसाइड की जरूरत है इस बारे में भी जानकारी है
- » इसके अलावा भूमि के हिसाब से कितनी सिंचाई करनी है इस बारे में भी बकायदा जानकारी दी गई है।

## वैज्ञानिकों के नंबर भी कराए गए मुहैया

किसान भाई अगर इससे अतिरिक्त भी कोई जानकारी चाहते हैं या ऐप से मिली जानकारी के बाद भी उनकी समस्याएं भी दूर नहीं होती हैं। तो इस ऐप में संस्थान के डायरेक्टर से लेकर साइंटिस्ट तक का मोबाइल नंबर और मेल आईडी भी दिया गया है। किसान भाई उनसे सीधे संपर्क कर अपनी परेशानियां दूर कर सकते हैं।



## इक्षु केदार मोबाइल ऐप

इस मोबाइल ऐप की मदद से गन्ने की फसल में अगली सिंचाई की तिथि पता चलती है, जिससे बार बार की जाने वाली अनावश्यक सिंचाई से बचा जा सकता है। यह ऐप गन्ना खेती की समान्य दशाओं में उत्तर भारतीय राज्यों के मौसम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उत्तर भारतीय जलवायु के लिए गन्ने की फसल में लाभप्रद उपज को लक्ष्य करके, वैज्ञानिक गणना के आधार पर इस मोबाइल ऐप इक्षु केदार को भाकूअनुप-भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ द्वारा विकसित किया गया है। इसके उपयोग से गन्ने की फसल में अगली सिंचाई की तिथि पता चलती है, जिससे बार-बार की जाने वाली अनावश्यक सिंचाई की बचत होती है। अलग-अलग मौसम में बोई गई गन्ने की फसल के लिए दो सिंचाईयों के बीच का अंतराल अलग-अलग होगा इसलिए गन्ना बुवाई की तिथि तथा पिछली सिंचाई की तिथि अवश्य अंकित करें। विशेष परिस्थितियों जैसे लवणीय या क्षारीय मृदा, जल भराव वाले क्षेत्र तथा अति भारी अथवा बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में इसका उपयोग संस्तुत नहीं है।

## कृष-ई निदान ऐप

कृष-ई निदान ऐप एक रियल टाइम में सक्रिय फसल रोग पहचान करने वाला ऐप है, जो एक किसान को 20 से अधिक सबसे लोकप्रिय फसलों को प्रभावित करने वाले सामान्य पौधों की बीमारियों और कीटों की पहचान करने में मदद करेगा। ऐप कीट/रोग के संक्रमण की सही और तुरंत पहचान करने में मदद करता है और रियल टाइम समाधान पेश करता है। कृष-ई निदान की टैगलाइन है फोटो लो, रोग जानो। यह दो अत्याधुनिक तकनीकों-इमेज रिकग्निशन और मशीन लर्निंग को नियोजित करने वाला एक अति विशिष्ट मोबाइल ऐप सॉल्यूशन है। किसानों को बस ऐप पर अपनी फसल के प्रभावित क्षेत्र की स्पष्ट तस्वीर अपलोड करनी होगी। फिर यह एप्लिकेशन कुछ ही सेकंड में फसल को प्रभावित करने वाले कीट या रोग की पहचान कर देगा और निवारक तथा उपचारात्मक उपायों के बारे में बताएगा।

फाइनल में अमेरिका की एमिली शिल्सन से हार का सामना करना पड़ा, भारत का इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में 7वां रजत पद

**फुटबाल के पहले ही राउंड में निकाल लिया था स्टे**

**किसान की बेटी का गरीबी में बीता बचपन, चुनी कुश्ती तो मिले ताने, फिर भी नहीं हारी हिम्मत, टोकियो में जीता सिल्वर**

दयानंद चौतसिया, छिंदवाड़ा।

मध्यप्रदेश की दंगल गर्ल शिवानी पवार ने अंडर 23 अंतरराष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलो वेट में सिल्वर मेडल जीता है। फाइनल में अमेरिका की एमिली शिल्सन से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि शिवानी शुरुआत में आगे रहीं, लेकिन एमिली ने वापसी करते हुए इसे जीत लिया। भारत का इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में 7वां सिल्वर मेडल है। टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले रवि दहिया और बजरंग पुनिया ने भी सिल्वर मेडल जीता है।

शिवानी ने अंडर 23 अंतरराष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल मिला है। गुरुवार रात सर्बिया में वे फाइनल में अपने प्रतिद्वंद्वी से हार गईं। शुरुआत में 4-2 से आगे चल रही थी, बाद में बाय फॉल की वजह से हार गईं। शिवानी साधारण किसान परिवार की बेटी हैं। छिंदवाड़ा के उमरेट में घर टपरे का है। पापा नंदलाल पवार सिर्फ तीन एकड़ जमीन के किसान हैं। तीनों बेटियों और बेटे को उनका करियर खुद चुनने दिया। समाज के तानों के बाद भी बेटियों को रेसलिंग के लिए पूरा सपोर्ट किया।



**8वीं तक फुटबॉल और रनिंग का शौक था**

शिवानी पवार की मां पुष्पा पवार ने बताया कि शिवानी की स्कूलिंग पंडित विशंभर नाथ हाईस्कूल उमरेट में हुई। 8वीं क्लास तक उसे फुटबॉल और रनिंग का शौक था। स्कूल कोच कलशराम मर्सकोले ने पहले उसे फुटबॉल में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। शिवानी ने फुटबॉल के पहले ही राउंड में स्टे निकाल लिया। कॉम्पिटिशन से वापस आने पर कोच ने उसे रेसलिंग करने की सलाह दी। कोच ने उनसे और शिवानी के पिता से भी इसे लेकर बात की। कोच ने कहा कि शिवानी को वह रेसलिंग में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। हमने भी कहा- हमें कोई प्रॉब्लम नहीं।

**समाज के ताने भी मिले**

शिवानी की मां ने कहा कि जब हमने शिवानी को कुश्ती में भेजने का फैसला किया तो शुरुआत में समाज के ताने भी मिले। लोग कहा करते थे कि लड़की है, लड़की को कोई कुश्ती में भेजता है क्या। वैसे तो शिवानी का अब छिंदवाड़ा आना कम ही होता है, लेकिन फिर भी जब भी होता है, यही लोग अब सोचते हैं कि शिवानी से मुलाकात हो जाए और बातचीत कर लें। शिवानी की छोटी बहन भारती पवार का कहना है कि सामाजिक दबाव के बाद भी हमारे माता-पिता दोनों ने ही कभी मुझे कुश्ती और बाहर निकलने से मना नहीं किया। हमें हमेशा प्रोत्साहित किया।

मंत्री गोविंद राजपूत ने दमोह से की शुरुआत, गांव-गांव में किसानों का रिकॉर्ड करेंगे दुरुस्त

# प्रदेश में शुरू हुआ राजस्व पखवाड़ा महाभियान

संवाददाता, भोपाल।

मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करने का कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए राजस्व पखवाड़ा महाभियान चलाया जा रहा है, जो 15 नवंबर तक प्रदेश में जारी रहेगा। इसके तहत करोड़ों की संख्या में लोगों के राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किए जाएंगे। प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत ने दमोह जिले के ग्राम लक्ष्मण कुटी में राजस्व पखवाड़ा कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में राजस्व विभाग के मूल उद्देश्य एवं राजस्व संबंधी समस्याओं निवारण के लिए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर इस महा अभियान की शुरुआत की गई और इसके तहत गांव-गांव जाकर यह कार्य किया जाएगा। इस महाअभियान का आगाज दमोह के लक्ष्मण कुटी इलाके से हुआ। इस महा अभियान के साथ ही प्रधानमंत्री आवास के लिए नागरिकों को जमीन और उसका पट्टा भी दिया जाएगा। इसकी शुरुआत भी मंत्री ने दमोह से की। दोनों योजनाओं को कैबिनेट की ओर से मंजूरी मिल गई है। इसका लाभ करोड़ों की संख्या में लोगों को मिलेगा।



आम नागरिक खासतौर पर ग्रामीण हिस्से में रहने वाले लोगों को अपने राजस्व अभिलेख सुधार कराने के लिए तहसील दफ्तरों में भटकना पड़ता है, जिसे देखते हुए विभाग ने यह फैसला किया है कि प्रदेश के करोड़ों लोगों के रिकॉर्ड दुरुस्ती का काम उनके घर जाकर पूरा किया जाएगा। गोविंद सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री

**छोटी-बड़ी बहू जैसे शब्द हटेंगे**

आयुक्त भू-अभिलेख ज्ञानेश्वर बी पाटील ने बताया कि राजस्व रिकॉर्ड में बहुत से भूमि स्वामी के नाम रिकॉर्ड में दर्ज हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। नामांतरण के आवेदन प्राप्त नहीं होने की वजह से रिकॉर्ड में सुधार नहीं हो पाता है। कई जगह रिकॉर्ड में भूमि स्वामी के रूप में बड़ी बहू, छोटी बहू, मझाले भैया आदि प्रचलित नाम दर्ज हैं। इस त्रुटि को इस अभियान में सुधारा जाएगा। प्रदेश में आठ लाख 96 हजार 984 खसरे नंबर ऐसे पाए गए हैं, जिनमें भूमि स्वामी के नाम नहीं हैं, जबकि नियमानुसार खसरे में शासकीय भूमि या निजी भूमि है तो भूमि स्वामी का नाम दर्ज होना चाहिए। 16 लाख सात हजार 595 खसरों के मूल नंबर और बटांकन, दोनों ही रिकॉर्ड में दर्ज हैं। इसकी वजह से गांव का क्षेत्रफल अधिक दिखाई देता है। जबकि, जब भूमि का बटांकन हो चुका है तो नए नंबर से रिकॉर्ड दुरुस्त होना चाहिए। इन प्रकरणों में अनावश्यक खसरा नंबरों को हटाया जाएगा। दो लाख 27 हजार खसरे ऐसे हैं, जिनका वर्गीकरण किसी भी वर्ग में नहीं किया जाएगा है। अभियान में इन्हें चिन्हित करके वर्गीकरण किया जाएगा। खसरों में सुधार के लिए बाकायदा आवेदन लिए जाएंगे।

**उज्जैन में बड़े स्तर पर सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन**

वंदना वृजेश परमार, उज्जैन।

सरकारी बिल्डिंग और बंजर जमीन पर बिजली की खेती हो रही है। बारिश कम और कोयले के संकट के बीच यह अच्छी खबर है कि उज्जैन में सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन बड़े स्तर पर होने लगा है। जिले के ऐसे गांव जहां की जमीन बंजर है, उसका उपयोग बिजली के उत्पादन में किया जा रहा है। जिले में सोलर पॉवर पैक के तहत ऊर्जा विकास

निगम द्वारा लगाए गए सोलर प्लांट से पांच साल में 770.50 करोड़ यूनिट का बिजली का कुल उत्पादन हुआ है। जिला अस्पताल सहित अन्य सरकारी अस्पताल, पीएचई व स्कूल तथा उच्च शिक्षा विभाग में 1.38 करोड़ यूनिट का उत्पादन हुआ है। तराना तहसील के गांव कड़ोदिया व सिद्धपुर निपानिया तथा डेलची में 2020-21 में 127.75 करोड़ यूनिट बिजली बनी।

**बंचर भूमि पर हो रही बिजली की खेती**

बंचर भूमि पर हो रही बिजली की खेती

**बंच रहे बिजली-** अधिकारियों ने बताया सोलर पावर पैक्स योजना के तहत प्राइवेट कंपनियों ने यहां पर सोलर प्लांट लगाए गए हैं, जो पावर परसेस एग्रीमेंट के तहत बिजली कंपनी को बंच रही है। जिले में कैप्टिव पावर सहित 2.5 मेगावॉट बिजली एमपीयूवीएन से तथा 127.96 नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की मेगावॉट बिजली सोलर पावर पैक्स से और विंड पावर से 107.40 मेगावॉट, कुल 235.86 मेगावॉट बिजली पैदा हो रही है। **577.85 करोड़ यूनिट बिजली की बचत-** सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन होने से बिजली कंपनी का लोड कम होता जा रहा है और उसे अतिरिक्त बिजली भी मिल रही है। 577.85 करोड़ यूनिट की बचत हुई है।

## केवीके झाबुआ में कड़क नाथ वेबसाइट लॉन्च

संवाददाता, झाबुआ। मप्र के 66वें स्थापना दिवस के पावन पर्व के अवसर पर कृषि विज्ञान केन्द्र झाबुआ द्वारा कड़कनाथ वेबसाइट लॉन्च का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि इंदरसिंह परमार, मंत्री स्कूल शिक्षा मंत्री, विशिष्ट अतिथि लक्ष्मण सिंह नायक, जिला अध्यक्ष, भाजपा झाबुआ, शांतिलाल बिलवाल, पूर्व विधायक झाबुआ उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में केवीके झाबुआ व पशुपालन विभाग के समस्त अधिकारी, कर्मचारी एवं जिले के ग्रामों से 150 महिला पुरुष उपस्थित थे। कड़कनाथ वेबसाइट को लॉन्च करने का उद्देश्य जिले के कड़कनाथ पालकों को ई-कॉमर्स

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। इससे किसान व जिले के छोटे कड़कनाथ व्यवसायी आज की तकनीक भरी ऑनलाइन दुनिया के साथ कदम से कदम मिला कर चल सके व इससे संबंधित उत्पादों को ग्लोबल बाजार में बेच सकते हैं और आत्मनिर्भरता की राह में एक कदम बढ़ा सकते हैं। इस वेबसाइट के निर्माण में विशेष तकनीकी सहयोग संत कुमार चौबे, जिला लोक सेवा प्रबंधक, जिला प्रशासन झाबुआ, विषय वस्तु विशेषज्ञ सहयोग डॉ. अमर सिंह दिवाकर, डॉ. चंदन कुमार, डॉ. अमित दोहरे व सहयोगी विभाग पशुपालन एवं डेयरी विभाग झाबुआ का विशेष योगदान रहा।

## आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

## जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

**संपर्क करें**

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195  
 शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277  
 नरसिंहपुर, प्रहलाद चौधरी-9926569304  
 विदिशा, अवधेश दुबे-9425148554  
 सागर, अनिल दुबे-9826021098  
 राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827  
 दमोह, बंटी शर्मा-9131821040  
 टीकमगढ़, नीरज जैन-9893583522  
 रायगढ़, गजराज सिंह मीणा-9981462162  
 बैतूल, सतीश साहू-898277449  
 मुरैना, अवधेश दण्डोतिया-9425128418  
 शिवपुरी, खेमराज मोर्य-9425762414  
 मिण्ड-नीरज शर्मा-9826266571  
 खरगोन, संजय शर्मा-7694897272  
 सतना, दीपक गौतम-9923800013  
 रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670  
 रतलाम, अमित निगम-70007141120  
 झाबुआ-नोमान खान-8770736925



कार्यालय का पता:- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र, संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589